सख्ती से काम करती रहेगी पुलिस

- **उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने की दिशा में अभी और क्या चुनौतियां मानते हैं ?**

प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना हमारी प्राथमिकताओं में रहा है। 173 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। प्रदेश के चिह्नित 50 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही 3187 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त व ध्वस्त की गई हैं। हमने हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए हमने पुलिस रिफार्म और पारदर्शी तरीके से 1.60 लाख भर्तियां और उनकी ट्रेनिंग कराई है। उन्हें आधुनिक शस्त्र भी उपलब्ध कराए गए। अपराध की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए हर रेंज में साइबर थाने की व्यवस्था, एफएसएल लैब्स की स्थापना की गई है। साथ ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साइंसेज की स्थापना की जा रही है। इससे कानून व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ रखने में सफलता मिली। मैं स्पष्ट करता हूं कि प्रदेशवासियों के हित में चाहे अन्य शहरों में भी कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करना हो या फिर और भी कोई कड़ा निर्णय करना हो, वह तत्काल करेंगे।

- **कोरोना संक्रमण के बाद अस्पतालों में इन्फ्रास्ट्रक्चर तो खूब बढ़ा लेकिन पर्याप्त डाक्टर नहीं। सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के करीब 19 हजार पद में छह हजार पद खाली हैं। मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना है?**

प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज तो बनाए ही जा रहे हैं, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी संस्थान खोले जा रहे हैं। तकनीक का इस्तेमाल कर टेली मेडिसिन को बढ़ावा भी दे रहे हैं। निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले रहे हैं।

- **20 राज्य विश्वविद्यालय और अब 33 निजी विश्वविद्यालय हैं। फिर भी बढ़ती आबादी के लिहाज से इनकी संख्या कम है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए आप और क्या करने वाले हैं?**

हमारी कोशिश है कि प्रत्येक मंडल मुख्यालय में एक विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय खोलने में निजी क्षेत्र भी दिलचस्पी दिखा रहा है। 1516 विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव आए हैं। संबंधित टीमों द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है।

- **बरेली और शाहजहांपुर वाली बेल्ट में लोग एम्स मांग रहे हैं। यदि बनता है तो अमरोहा और संभल, रामपुर तक के लोगों के लिए यह बड़ा उपहार होगा।**

शाहजहांपुर, बदायूं में हमने मेडिकल कालेज दिए हैं और पीलीभीत में बन रहा है। फिर भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की अपेक्षा तो स्थानीय लोगों को होती ही है। यह ठीक भी है और चूंकि दोनों जगह केंद्र और प्रदेश में हमारी ही सरकारें हैं तो इसके लिए प्रयास किया जाएगा।

शहरी बेरोजगारी पर हमारा पूरा ध्यान है

- **आपको नहीं लगता शहरी बेरोजगारी बड़ी समस्या बन चुकी है और धीरे-धीरे और विकराल रूप लेती जा रही है। केंद्र सरकार ने कौशल विकास की जो हालिया रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार तो केवल दस प्रतिशत युवाओं को ही औद्योगिक संस्थानों में रोजगार मिल सका है। इससे निपटने की क्या योजना है?**

हमने 10 लाख युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा था और इनमें से 40 प्रतिशत से अधिक को रोजगार मिल चुका है। हम सीएम अप्रेंटिसशिप योजना चलाते हैं जिसके माध्यम से अब तक 62 हजार युवाओं को इंसेंटिव दिया जा चुका है।

> प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से कृषकों की लागत कम करने के उद्देश्य से करीब 2.60 करोड़ किसानों के बीच 51,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक गन्ना किसानों को 1.90 लाख करोड़ के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 15 हजार सोलर पंप का आवंटन किया जा रहा है। 24 लाख से अधिक किसानों को किसान मानधन योजना के तहत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ गया है। खेतीबाड़ी के प्रयोग में ड्रोन के प्रयोग की शुरुआत की गई है। कृषि स्नातकों को 40-50 प्रतिशत अनुदान पर ड्रोन दिए जा रहे हैं।

कानपुर की हमें पूरी चिंता है

- **नोएडा के बाद कानपुर सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर है। होजरी, चमड़ा, कपड़े, गल्ले का बड़ा काम है वहां, लेकिन शहर की हालत नहीं सुधर रही। दिल्ली जाने के लिए आगरा एक्सप्रेस पर चढ़ना हो तो अब भी ढाई से तीन घंटे लग जाते हैं। कई बड़े उद्योग कानपुर से पलायन कर चुके हैं। कानपुर की प्रगति बिना प्रदेश की प्रगति कैसे हो सकती है?**

कानपुर की पूरी चिंता है हमें और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। एक एयरपोर्ट वहां चालू हो गया है और लखनऊ से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। उसके बनने के बाद 45 मिनट में कानपुर पहुंचा जा सकेगा। मेट्रो वहां चल ही रही है और आप जरा डिफेंस कारिडोर को गति पकड़ने तो दें। फिर देखिएगा कानपुर में किस तेजी से बदलाव होता है। डिफेंस कारिडोर में सर्वाधिक भागीदारी कानपुर की ही होने वाली है। उस शहर को हम पीछे नहीं छूटने दे सकते। उस पर हमारा पूरा ध्यान है। देखते जाइए। कानपुर को हम उसके पुरातन वैभव से भी आगे ले जाएंगे।

- **पर्यटन बड़ा उद्योग है और इस पर इस बीच काफी काम भी हुआ है, लेकिन जैसे प्रयागराज में संगम है तो केवल कुंभ या माघ मेले में ही वहां भीड़ जुटती है। प्रदेश की इतनी बड़ी सम्पदा है संगम, किंतु ऐसा लगता है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा?**

सहमत हूं आपसे, पर एक तो कठिनाई यह है कि वह सारा क्षेत्र सेना के अधीन है और हमें केवल मेले के समय मिल पाता है। तो हम वहां स्थायी कुछ नहीं कर सकते हैं और ऊपर से गंगा की धारा वहां हर साल बदल जाती है तो काशी या अयोध्या की तरह वहां पक्के घाट भी नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर भी संगम को ध्यान में रखते हैं।

- **केंद्र सरकार मोटे अनाज (मिलेट्स) पर बहुत जोर दे रही है। क्या आपको लगता कि इनका प्रयोग बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के किसानों की माली दशा में भी सुधार होगा?**

बिल्कुल होगा सुधार। बुंदेलखंड को तो बहुत लाभ होगा। कम पानी लगेगा और उपज के दाम भी अधिक मिलेंगे। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मोटे अनाज के लिए हम जो प्रोत्साहन योजनाएं लाने जा रहे हैं, वे किसानों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी।

- **एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में क्या कुछ हो रहा है?**

प्रदेश में नौ एयरपोर्ट संचालित हैं। 10 अन्य एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर, वाराणसी व लखनऊ में संचालित है। जेवर व अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इनके बनने के बाद पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य यूपी होगा। साथ ही अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर (सोनभद्र) व श्रावस्ती में एयरपोर्ट के संचालन के लिए एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से समझौता किया गया है।

- **रामलला का भव्य मंदिर और दिव्यधाम गलियारा का काम कब पूरा हो रहा है?**

दोनों ही काम तेजी से हो रहे हैं। गुणवत्ता और भव्यता के साथ सभी काम समय पर पूरे कर लिए जाएंगे।

सभी फोटो : रंगनाथ तिवारी

- **आपके पिछले कार्यकाल में एक जनपद एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) की शुरुआत से राज्य के निवेश में क्या अंतर आया है?**

बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। यह पहली बार हुआ कि हर जिले के उत्पाद को व्यापक पहचान मिली। हमारा निर्यात लगभग 1.60 लाख करोड़ का है और इसमें 80 प्रतिशत से अधिक भागीदारी एमएसएमई की है जिसमें ओडीओपी की बड़ी भूमिका है। सबकी जियो टैगिंग की गई और इसका भी बड़ा लाभ मिला। अब हम इसका भी दायरा भी बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये का हो गया है। हमने 83 हजार ओडीओपी कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें टूलकिट बांटें। आज आनलाइन ईकामर्स पोर्टल पर 20 हजार से अधिक ओडीओपी के उत्पादों की बिक्री हो रही है।

- **उत्तर प्रदेश के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन एक बड़ी चुनौती रही है। निवेशक पश्चिमी यूपी जैसा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। कृषि, बागवानी जैसे प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर भी समानुपातिक नहीं रही है। अब इन क्षेत्रों में भी निवेश सुनिश्चित करने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?**

पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने से कैसे उस क्षेत्र के विकास में तेजी आई है यह आप खुद देख रहे होंगे। हमने क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए ऐसी लचीली और व्यावहारिक औद्योगिक नीतियां भी बनाई हैं जिससे निवेशक, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए आगे आए। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को झांसी से भी जोड़ेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार होने से आने वाले समय में यह दोनों क्षेत्र भी विकास के मामले में किसी से पीछे नहीं रहेंगे।

- **आप इन्वेस्टर्स समिट कर रहे हैं और पिछली बार के अनुभवों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसके परिणाम सकारात्मक होंगे, लेकिन एक ट्रिलियन डालर का लक्ष्य पाने के लिए प्रदेश के समग्र विकास का प्रयास करना होगा। समिट के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और क्या उसका भी कोई रोडमैप बना है क्योंकि यही कारण है कि बड़ा निवेश नोएडा से आगे नहीं बढ़ता?**

आप देखें कि बेहतर कनेक्टिविटी से अब दिल्ली से बलिया सात-आठ घंटे में लोग पहुंच जा रहे हैं। लखनऊ हो या दिल्ली कहीं से भी चित्रकूट पहुंचना बहुत सुगम हो गया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि इससे अंतर पड़ेगा। औद्योगिक प्रगति के लिए सबसे अनिवार्य शर्त होती है कनेक्टिविटी। अब कहीं से कहीं सरलता से और कम समय में पहुंचा जा सकता है। फिर बिजली अब बहुत है और कानून व्यवस्था तो है ही अच्छी। तो भरोसा जगा है निवेशकों का हम पर। अभी तक पश्चिम उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वांचल और बुंदेलखंड विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूटे हुए थे। न वहां सड़कें थीं और न बिजलीपानी, लेकिन अब परिवर्तन हो रहा है। ललितपुर में फार्मा कंपनियां पहुंच रही हैं। चित्रकूट आगे बढ़ रहा है और कुशीनगर जैसे दूर दराज के जिले में हवाईअड्डा शुरू हो गया है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, पर अब हरदोई में वेब्बे स्काट बनने लगी है। ये चंद उदाहरण हैं, पर इनसे आप समझ सकते हैं कि हमारा जोर चतुर्दिक विकास पर है। थोड़ा समय बीतने दें तो देखिएगा अब तक उपेक्षित रहे ये दोनों अंचल किस तरह आगे निकल कर आते हैं। हमारी कोशिश है कि निवेशक पूरे प्रदेश में पहुंचें।

> हमने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित कर रखा है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नगरीय निकायों के चुनाव सुनिश्चित किए जाएंगे।

समिट से जनप्रतिनिधियों को भी लाभ

- **पिछले दिनों आपने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उनकी सर्वाधिक शिकायतें किससे संबंधित रही हैं?**

हमने प्रदेश के विकास में योगदान को लेकर सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों के संबंध में अपनी बात रखी। हर एक जिले में इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन में जनप्रतिनिधियों को भी लगाया गया है। आखिर जिले में निवेश से होने वाले विकास का फायदा तो जनप्रतिनिधियों को भी मिलना ही है।